भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1426
मंगलवार, 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण,1948(शक) को उत्तरार्थ

कृषि सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना

+1426. **श्री जय प्रकाशः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता, शासन मानकों और व्यावसायिक प्रदर्शन का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कितनी पीएसीएस स्पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया गया है, उन्हें नई आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है और डिजिटल बैंकिंग तथा ई-शासन मंच से जोड़ा गया है; और

(ग) किसानों को भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन और कृषि निविष्ट की आपूर्ति सहित एकीकृत कृषि सेवाएँ प्रदान करने में पीएसीएस को सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हां, मान्यवर । सरकार ने देश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में पारदर्शिता, वित्तीय व्यवहार्यता एवं आय बढ़ाने हेतु प्रशासनिक सुधार की पृष्ठभूमि में कई कदम उठाए हैं । पैक्स की शासन, पारदर्शिता और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार के लिए, हितधारकों के परामर्श से **पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां** तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यों को परिचालित की गई है । ये आदर्श उपविधियां पैक्स को **25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप** करने में सक्षम बनाती हैं, अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही के माध्यम से शासन में सुधार लाती हैं और महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ सदस्यता को अधिक समावेशी बनाती हैं । मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार **32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने आदर्श उपविधियां अपना ली हैं या अपनी मौजूदा उपविधियो को आदर्श उपविधियों के साथ संरेखित कर लिया है ।**

इसके अलावा, पैक्स की वित्तीय संधारणीयता और व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार के लिए मंत्रालय विभिन्न पहलों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. कॉमन ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यशील पैक्स का कंप्यूटरीकरण;

ii. विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में पैक्स का विविधीकरण;

iii. अनाच्छादित पंचायतों में नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना;

iv. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पहल के अधीन पैक्स स्तर पर कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण; और

v. प्रभावशाली सेवा प्रदाय के लिए पैक्स का डिजिटल और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण।

(ख): भारत सरकार ₹2,516 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना कार्यान्वित कर रही है जिसे अब बढ़ाकर ₹2925.39 करोड़ कर दिया गया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है । इस परियोजना के अधीन हुई प्रगति का राज्य-वार ब्योरा **संलग्नक- 'क'** पर दिया गया है ।

पैक्स द्वारा मॉडल उपविधियों के अंतर्गत संचालित विविध गतिविधियों की स्थिति (दिनांक 15.07.2026 तक) निम्नानुसार है:

15.07.2026 तक, 64,159 पंजीकृत पैक्स में से 55,514 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में कार्य कर रहे हैं; प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) योजना के अंतर्गत पैक्स से 4,275 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,255 को प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, 900 को औषधि लाइसेंस प्राप्त हुए हैं, 846 को स्टोर कोड आवंटित किए गए हैं तथा 645 केंद्र क्रियाशील हो चुके हैं; उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्यरत 48,461 पैक्स में से 38,974 को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में उन्नत किया गया है; 10 राज्यों में 1,480 पैक्स को जल समितियों के रूप में चयनित किया गया है, जिनमें से 118 ने ऋण वसूली कार्य प्रारंभ कर दिया है; तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 394 पैक्स ने पेट्रोल/डीजल के खुदरा आउटलेट हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है तथा 13 आउटलेट चालू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 5 राज्यों में थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप लाइसेंस धारित करने वाले 115 पैक्स ने अपने आउटलेट को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने पर सहमति दी है, जिनमें से 62 खुदरा आउटलेट चालू हो चुके हैं।

मंत्रालय ने कृषि ऋण एवं सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने हेतु पैक्स ईआरपी प्रणाली का विभिन्न राज्यों के डिजिटल एवं ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण करने के लिए भी कदम उठाए हैं। आंध्र प्रदेश में, पैक्स ईआरपी का एकीकरण ई-गवर्नेंस सेवाओं, धान खरीद, एलपीजी, मार्कफेड, आंध्र प्रदेश सरकार के IGRS पंजीकरण एवं स्टाम्प पोर्टल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), ई-क्रॉप तथा मुख्य आयुक्त भू-प्रशासन (CCLA) प्लेटफॉर्म के साथ किया गया है; बिहार में, आधार-सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (AePDS) एवं ई-सहकारी के साथ एकीकरण किया गया है; छत्तीसगढ़ में, एकीकृत किसान पोर्टल, समिति पंजीकरण मॉड्यूल, खाद्य पोर्टल, मार्कफेड, भुइयां सिटिजन यूआई तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है; गुजरात में, गुजरात सहकारी पोर्टल एवं Any ROR (भूमि अभिलेख) गुजरात पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है; मध्य प्रदेश में, एमपी भूलेख एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के साथ एकीकरण किया गया है; राजस्थान में, ई-धरती, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर (RSDC), सिंगल साइन-ऑन (SSO),

ई-पीडीएस, जन सूचना पोर्टल एवं राजसहकार पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है; उत्तर प्रदेश में, यूपी भूलेख पोर्टल के साथ एकीकरण पूर्ण किया गया है तथा तमिलनाडु में, व्यापक ऑडिट प्रबंधन प्रणाली (CAMS) के साथ एकीकरण किया गया है।

(ग): पैक्स द्वारा संचालित विविध गतिविधियों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा ऐसे कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जिनसे पैक्स को एकीकृत कृषि सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। इनका विवरण निम्नानुसार है:

सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का सृजन किया जाना है, जिनमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं। यह कार्य भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किया जा रहा है, जैसे कि कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) आदि। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत देशभर में 1,015 पैक्स की पहचान गोदाम निर्माण हेतु की गई है तथा 313 पैक्स में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे कुल 1.80 लाख मीट्रिक टन (LMT) की भंडारण क्षमता सृजित हुई है।

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी उत्पादों एवं सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विपणन सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) की स्थापना भी की है। अब तक, NCEL ने 50 कृषि जिंसों के 14,89,102 मीट्रिक टन का निर्यात 38 देशों को किया है, जिसका कुल मूल्य ₹5,866.10 करोड़ है। इसी प्रकार, जैविक उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना की गई है। NCOL "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के अंतर्गत जैविक उत्पादों का विपणन करता है और इसके उत्पाद नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में 1100 से अधिक खुदरा आउटलेट्स तथा ई-कॉमर्स एवं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। किसानों को गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित एवं किफायती बीज (इनपुट सेवाएँ) उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की गई है। अब तक, BBSSL ने 6,07,620 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन किया है तथा अपने विस्तृत सहकारी नेटवर्क के माध्यम से 'भारत बीज' ब्रांड लगभग 66 लाख किसानों तक पहुँच चुका है, जिससे किसानों की गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीजों तक पहुँच में सुधार हुआ है।

संलग्नक- 'क'

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	अनुमोदित पैक्स	हार्डवेयर डिलीवर किए गए	ईआरपी ऑनबोर्ड किया गया
1	अंडमान और निकोबार	46	46	46
2	आंध्र प्रदेश	2037	2021	2021
3	अरुणाचल प्रदेश	139	14	14
4	असम	850	709	581
5	बिहार	4495	4477	4482
6	छत्तीसगढ़	2028	2028	2028
7	दमन और दीव	9	4	4
8	गोवा	86	58	55
9	गुजरात	6216	5754	5760
10	हरियाणा	710	710	710
11	हिमाचल प्रदेश	1885	1789	1598
12	जम्मू और कश्मीर	708	537	537
13	झारखंड	2797	1500	1491
14	कर्नाटक	5894	5491	4590
15	लद्दाख	10	10	10
16	मध्य प्रदेश	5455	4536	4536
17	महाराष्ट्र	12178	12000	12033
18	मणिपुर	308	196	214
19	मेघालय	330	108	103
20	मिजोरम	99	49	45
21	नागालैंड	231	231	142
22	ओडिशा	4240	0	0
23	पॉन्डिचेरी	45	45	44
24	पंजाब	3482	3456	3454
25	राजस्थान	8525	6781	6933
26	सिक्किम	131	107	107
27	तमिलनाडु	4561	4532	4481
28	त्रिपुरा	475	268	268
29	उत्तर प्रदेश	6257	3581	3219
30	उत्तराखंड	1216	670	668
31	पश्चिम बंगाल	4187	4167	3512
	कुल	**79630**	**65875**	**63686**